कर्मचारी की मौत के मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट कर्मचारी की जलने से हुई मौत के मामले में भांकरोटा थाना पुलिस ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ हत्या, बलात श्रम कराना, बंधक बनाना और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने गत दिनों घटना को आत्मदाह बताया था। वहीं दूसरी ओर न्यायिक कर्मचारियों ने कहा है कि अन्य मांगों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से वार्ता की जाएगी और सभी जिला अध्यक्षों की सहमति से सामूहिक अवकाश पर निर्णय लिया जाएगा।

मृतक सुभाष मेहरा की बहन की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट में पदस्थापित उसके भाई सुभाष को इस कोर्ट के न्यायाधीश अपने घर पर बंधक बनाकर रखते थे और उससे जबरन घरेलू बेगार कराई जाती थी। वहां से परेशान होकर सुभाष कुछ दिनों पहले उसके घर आकर रुका था, लेकिन इस बीच पुलिसकर्मी उसे जबरन उठाकर ले गए। वहीं गत दस नवंबर को एक पुलिसकर्मी ने फोन कर सुभाष की तबीयत खराब होना बताकर बुलाया। पुलिसकर्मी सुभाष के परिजनों

न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट कर्मचारी की जलने से हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ ने सोमवार को रैली निकाली।

को न्यायाधीश चलाना के घर ले गए, जहां तीसरी मंजिल पर सुभाष का जला हुआ शव पड़ा था और शव की आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि घर पर एफएसएल टीम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान जज चलाना ने उन्हें कहा कि वह पावरफुल व्यक्ति है और उनके सारे काम और कर्ज माफ करवा देगा। वहीं उन्हें सुभाष का बिना सिम लगा मोबाइल लौटाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायाधीश कृष्ण

- **कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी**

स्वरूप चलाना और उनके परिजनों ने मिलकर सुभाष की हत्या की है। ऐसे में मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मामले में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने एफआईआर 28 दिन की देरी से दर्ज की है। पुलिस पहले ही इसे आत्मदाह बता चुकी है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर जलने से मौत हो गई थी। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मृतक के परिजनों को पचास लाख रुपए मुआवजा सहित एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बीते 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं।

गांधीनगर जयपुर स्टेशन का होगा विश्वस्तरीय पुनर्विकास

जयपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा गांधीनगर जयपुर स्टेशन का विश्वस्तरीय विकास किया जायेगा। इसके लिए 177.45 करोड रुपए का कार्य अवार्ड किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

- **दो नई बिल्डिंग के साथ ही एयर कॉनकोर्स एवं छत पर होगीं सुविधाऐं**

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबन्धक विजय शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन में गांधीनगर जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। वर्तमान गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर दो नई बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित है। सामने की ओर की मुख्य इमारत जी प्लस 2 बिल्डिंग बनाई जायेगी। मुख्य प्रवेश स्टेशन भवन में डिपार्चर लॉबी, वेस्टिबुल, बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच क्षेत्र, हेल्प डेस्क क्षेत्र, प्रस्थान हॉल, शौचालय, आरपीएफ कक्ष और हेड टीसी कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं होंगी। प्लेटफार्म 1 पर अनारक्षित प्रतीक्षालय, एक्जिक्यूटिव प्रतीक्षालय, खुदरा स्टालें, शौचालय, शिशु आहार कक्ष और प्लेटफार्म संख्या 1 पर आने वाले यात्रियों के लिए आगमन कक्ष होगा।

इस भवन का मेजेनाइन फर्श बनाया जायेगा। भूमि तल पर विभिन्न रेलवे कार्यालय एवं दूसरी मंजिल पर एक्सेस कंट्रोल, मेटल डिटेक्टर सिस्टम, बैगेज स्कैनर सिस्टम, अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्ष, रिटेल स्टॉल, मॉड्यूलर शौचालय, सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि होंगे। पहली मंजिल तक आसान पहुंच के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट एवं सीढ़ियां बनाई जाएंगी।

स्टेशन के दूसरे प्रवेश की इमारत जी प्लस 1 की होगी जिसमें टिकट काउंटरों के साथ हॉल, बुकिंग कार्यालय, बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच, प्रस्थान हॉल आदि होंगे तथा अन्दर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अनारक्षित प्रतीक्षा हॉल, शौचालय, बेबी केयर रूम, आरपीएफ थाना, आगमन हॉल, कुली रूम कक्ष होंगे। मुख्य प्रवेश द्वार पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त दो मंजिला भूमिगत बेसमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। मौजूदा फुट ओवर ब्रिज को नई वास्तु कला थीम के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा।

पुर्नविकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक एयर कॉनकोर्स प्रस्तावित है, जो दोनों इमारतों को प्लेटफार्मों के ऊपर से जोड़ते हुए बनाया जायेगा।

कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार में नंबर वन होने से निवेशक निवेश नहीं कर रहे प्रदेश में : भदेल

- **'केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था सकारात्मकता की ओर अग्रसर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने की कगार पर ला दिया है'**
- **'जब-जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब-तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है'**

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिता भदेल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, भाजपा द्वारा राजस्थान में चल रही जन आक्रोश यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस सरकार के राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता अब तंग आ चुकी है, भ्रष्टाचार की बानगी राजस्थान के पीपलखूंट में 1 हजार करोड़ रुपए की लाइम स्टॉन की माइंस को गहलोत सरकार ने मार्बल की माइंस बताकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए में ऑक्शन कर अपने चहेतों को दे दी। शेष बचा हुआ राजस्व यदि सरकारी के खजाने में आता तो राजस्थान के विकास की योजनाओं में काम आता, गहलोत सरकार ने सिफ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय प्रचलित योजनाओं के नाम बदले है।

भदेल ने कहा कि, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर वन पर है, जिसकी वजह से राजस्थान के विकास की गति बंद हो चुकी है। कांग्रेस सरकार जनता से वादों को नहीं पूरा कर उनके साथ वादाखिलाफी कर धोखा दे रही है। जब-जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब-तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बदहाली से मालूम चलता है कि मार्च 2019 तक प्रतिव्यक्ति कर्ज 38 हजार रूपए था, जो वर्तमान में दुगुना होकर लगभग 70 हजार रूपए हो गया है, यदि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसी गति से चलती रही तो 2023 तक प्रति व्यक्ति कर्जा 86 हजार रूपए हो जाएगा। भदेल ने कहा कि, राजस्थान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, कांग्रेस सरकार ने राज्य में कई वेलफेयर योजना बंद कर दी, साथ ही तीन वर्षो से किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम पूरे देश में सबसे अधिक है।

भदेल ने कहा कि, आज पूरे देश में सबसे अधिक मंडी टैक्स राजस्थान की किसानों पर लगाया गया है, बिजली के दरे महंगी होने से नए व्यापारियों ने कोई भी नई यूनिट राजस्थान में नहीं लगाकर दूसरे राज्यों में लगा रहे है। वर्ष 2021-22 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हर उपखंड मुख्यालय में औद्योगिक इकाइयां विकसित करेंगे लेकिन वर्तमान में 144 उपखंड मुख्यालय ऐसे है जहां कोई औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हुई है। केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था जहां सकारात्मकता की ओर अग्रसर है वहीं दूसरी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने की कगार पर लेकर आ गई है।

प्रदेश में केवल एक ही नया संक्रमित मिला सोमवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में पिछले करीब आठ महीने बाद सोमवार केवल एक ही नया करोना संक्रमित मिला है। तीसरी लहर के बाद यह नए संक्रमितों की अब तक की सबसे कम संख्या रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में केवल जयपुर में ही एक नया संक्रमित मिला है। हालांकि जांच रिपोर्ट में इसका पता सही नहीं होने से इसे ट्रेस नहीं किया जा सका है। उधर इस बीच जयपुर के अलावा अन्य किसी भी जिले में कोई भी नया संक्रमित नहीं पाया गया है। इससे पहले रविवार को प्रदेश में 9 रोगी पाए गए थे। राजय में सोमवार को कोई मरीज ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 68 हो गए हैं। इनमें 41 मरीजों का इलाज जयपुर में चल रहा है। प्रदेश में सोमवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

- **अन्य किसी भी जिले में नया संक्रमित सामने नहीं आया है**

आवासन आयुक्त ने 23.23 करोड़ रुपये का चैक ग्रेटर निगम को सौंपा

हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विक्रय की गई संपत्तियों से प्राप्त धनराशि में 15 फीसदी हिस्सा नगर निगम को दिये जाने का है प्रावधान

जयपुर। हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सोमवार को 23.23 करोड़ रुपये का चैक ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेन्द्र सोनी को सौंपा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के हस्तक्षेप के बाद यह रकम दी गई है। बताया जा रहा है कि बीते 15 वर्षों में दी गई यह सबसे बड़ी रकम है। दरअसल राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विक्रय की गई सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का 15 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम को दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन नगर निगम की कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने पर जो रकम खर्च करता है, वह इस 15 फीसदी राशि में से काटी जाती है।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने सोमवार को ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर महेन्द्र सोनी को 23.23 करोड़ रु. का चैक सौंपा।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि पिछले साल नगर निगम और हाऊसिंग बोर्ड की संयुक्त बैठक हुई थी। जिसमें वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान आवासन मंडल द्वारा विक्रय की गई सम्पत्तियों में निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व और हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की गई रकम का समायोजन हुआ था। इस समायोजन के बाद हाऊसिंग बोर्ड के 55.58 करोड रुपये नगर निगम पर बकाया है। इसके बावजूद उदारता के साथ नगर निगम को 11.11 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि का समायोजन करने के बाद 23 करोड़ 23 लाख 12 हजार रुपये नगर निगम को दिये गए हैं। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने आश्वस्त किया है कि वर्ष 2022-23 के लिए देय राशि का भी इस वित्त वर्ष के दौरान ही ग्रेटर निगम को भुगतान कर दिया जायेगा। ग्रेटर निगम कमिश्नर महेन्द्र सोनी ने बताया कि जेडीए कमिश्नर रवि जैन को भी 15 फीसदी हिस्सा राशि देने के लिए पत्र लिखा है। हाऊसिंग बोर्ड की तरह ही जेडीए द्वारा भी शहर में बेची जाने वाली संपत्तियों में 15 फीसदी हिस्सा राशि नगर निगम को देय है, अगर यह रकम मिलती है तो शहर की साफ-सफाई व अन्य विकास कार्य होंगे।

गैंगस्टर ने फोन कॉल पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

- **रकम नहीं देने पर राजू ठेहट की तरह 50 गोलियां मारने की धमकी दी**
- **बजाज नगर के बाद हरमाड़ा इलाके में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी का मामला सामने आया**

जयपुर (कासं)। बजाज नगर में व्यापारी को मिली धमकी के बाद अब हरमाड़ा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से धमकी मिली है। बदमाश ने 5 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर व्यापारी को 50 गोली मार गैंगस्टर राजू ठेहट जैसा हाल करने की धमकी दी है। गौरतलब है कि गत दिनों बजाज नगर इलाके निवासी व्यापारी से गोल्डी बराड़ के नाम से 2 करोड़ रूपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान की है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित के पास 10 दिसम्बर की शाम करीब साढ़े 6 बजे व्हाट्सप्प कॉल आया था। बदमाश ने खुद को बीकानेर निवासी गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया था। आरोपी ने धमकाते हुए पांच करोड़ रुपए की डिमांड की। नहीं देने पर 50 गोली मार कर राजू ठेहट जैसा हाल करने की धमकी दी। पीड़ित और रोहित के बीच काफी गाली गलौज हुई। इस दौरान बदमाश ने कुछ समय पहले हनुमानगढ़ में हुई एक हत्या का भी जिक्र किया। इसके बाद फोन काट दिया। डीसीपी, वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को सुरक्षा दे दी गई है। मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। वहीं, डीएसटी और सीएसटी टीम इस संबंध में कार्रवाई के लिए तैयार की गई है।

पीएम से मिले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

गांधीनगर/जयपुर। गुजरात के मुख्यमंत्रीभूपेन्द्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इत्यादि नेता शामिल हुये। जहां उन्होंने भूपेन्द्र पटेल और मंत्रिमंडल के साथियों से आत्मीय मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनायें दी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आत्मीय मुलाकात हुई और मार्गदर्शन मिला। पूनियां ने कहा कि गुजरात के नवनिर्वाचित सीएम भूपेंद्र पटेल से आत्मीय मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनायें दी।

कांस्टेबल भर्ती को लेकर जवाब मांगा

जयपुर। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 के सभी विज्ञापित पद नहीं भरने और अन्य अनियमितता बरतने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रेणुका चौधरी की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जोधपुर कमिश्नरेट के लिए 374 पदों के लिए भर्ती निकाली, लेकिन सिर्फ 365 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी।

साइबर अपराध रोकने के लिए दक्षता बढ़ाना जरूरी : डीजीपी

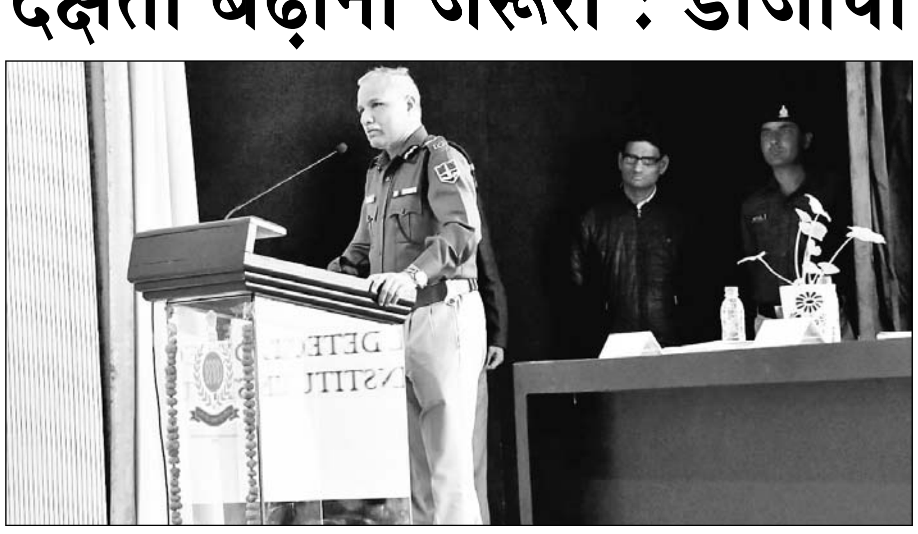

पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 12 से 23 दिसंबर तक आयोजित सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक प्रशिक्षण का सोमवार को उद्घाटन किया।

जयपुर। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक है। मिश्रा 12 से 23 दिसंबर तक आयोजित सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक प्रशिक्षण का आज यहां उद्घाटन किर रहे थे। राजस्थान पुलिस में नवगठित तकनीकी कोर ग्रुप के प्रतिभागियों की दक्षता अभिवृद्धि के लिए केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में 12 दिवसीय सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मिश्रा ने वर्तमान में नवीनतम तकनीकी की जानकारी की आवश्यकता एवं साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार एवं तकनीकी सेवाएं सुनील दत्त ने बताया कि राजस्थान पुलिस में स्थापित तकनीकी कोर ग्रुप के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कडी में यह दूसरा संस्करण है। ''तकनीकी कोर ग्रुप'' सीसीटीएनएस परियोजना के संचालन के साथ-साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर सुरक्षा एवं अन्य आईटी परियोजनाओं के साथ इंटीग्रेशन का कार्य प्रभावी रूप से करेगा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सचिन मित्तल, महा निरीक्षक पुलिस स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो शरत कविराज एवं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉ अमनदीप सिंह कपूर ने राजस्थान पुलिस में तकनीकी कोर ग्रुप की आवश्यकता के विषय में विचार प्रस्तुत किए।

'सरकारी पार्क की एक बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर पट्टा लिया'

दुर्गापुरा में महारानी फार्म रोड पर स्थित आयुष्मान सिंह नगर का मामला

- **जेडीए की प्रवर्तन टीम ने सरकारी पार्क में भूमाफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाया तो यह हकीकत उजागर हुई**
- **वर्ष 2012 में नगर निगम प्रशासन ने निविदा जारी करके इस पार्क में बाउंड्रीवाल बनवाई थी, बाद में भूमाफियाओं ने कब्जा कर अक्टूबर-2022 में इस जमीन का पट्टा ले लिया**
- **स्थानीय लोगों ने पार्क में कब्जे की शिकायतें पहले नगर निगम व जेडीए के जोन अधिकारियों को दी, जब सुनवाई नहीं हुई तो जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के पास पहुंचे थे**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। दुर्गापुरा इलाके में महारानी फार्म रोड पर स्थित आयुष्मान सिंह नगर में सरकारी पार्क की करीब एक बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर पट्टा भी ले लिया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी आंखें बंद किए बैठे रहे।

सोमवार सुबह जेडीए की प्रवर्तन टीम ने जब सरकारी पार्क में हो रहे अवैध निर्माण को बंद कराया तो नगर निगम प्रशासन की यह लापरवाही उजागर हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने जेडीए व नगर निगम के अफसरों से सांठगांठ कर यह अवैध कब्जा किया और पट्टा भी ले लिया। कई बार शिकायतों के बावजूद जब नगर निगम में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने जेडीए की प्रवर्तन टीम को सूचित किया।

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि महारानी फार्म रोड पर स्थित आयुष्मान सिंह नगर में करीब एक बीघा सरकारी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने शनिवार-रविवार की छुट्टी का फायदा

जेडीए की प्रवर्तन टीम ने दुर्गापुरा स्थित आयुष्मान सिंह नगर के सरकारी पार्क में किये गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

उठाकर अवैध निर्माण शुरू कर दिया था, जिसे सोमवार सुबह ध्वस्त किया गया था। रविवार को भी जेडीए टीम ने पार्क में पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराया था और औजार व अन्य सामान जब्त किया था।

रघुवीर सैनी ने बताया कि करीब 20 दिन पहले आयुष्मान नगर के रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत दी थी कि कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी पार्क की एक बीघा जमीन पर कब्जा करके पट्टा ले लिया है। अब यहां निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। इस पर जेडीए की प्रवर्तन टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिस पर सामने आया कि वर्ष 2012 में नगर निगम जयपुर ने निविदा जारी करके इस पार्क की चारदीवारी का निर्माण करवाया था। कुछ भूमाफियों ने अपराधिक कृत्य करके अक्टूबर-2022 में इस जमीन के पट्टे गलत ढंग से प्राप्त कर लिए। जिनके संबंध में अपेक्षित जांच करके आवश्यक कार्यवाही के लिए जोन-उपायुक्त को पत्र लिखा गया है।

जैसे ही सरकारी पार्क पर अवैध कब्जे की सूचना मिली थी तो हमने नगर निगम को यू.ओ. नोट लिखकर जोन उपायुक्त से व्यक्तिगत रिपोर्ट प्राप्त की। अब फिलहाल पार्क की जमीन पर बनाई जा रही बाउंड्रीवाल एवं अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है।